

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में "जल संरक्षण एवं संवर्द्धन मिशन" की आहूत बैठक दिनांक 15.05.2009 का कार्यवृत्त ।

स्थान: मुख्य सचिव सभा कक्ष

समय: प्रातः 11:00 बजे

उपस्थिति: (संलग्नक के अनुसार)

पेयजल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्द्धन कार्यों में प्रगति लाने हेतु मिशन की बैठक शासनादेश संख्या 360/ ए.पी.एस./ स.प्र.जे.ज./ 2009 पेयजल विभाग देहरादून दिनांक 11 मई, 2009 के क्रम में आयोजित की गयी ।

सर्वप्रथम सचिव पेयजल, उत्तराखण्ड शासन द्वारा मुख्य सचिव महोदय एवं उपस्थित सदस्यों एवं अधिकारियों का स्वागत कर, पेयजल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्द्धन की प्रगति प्रस्तुत करने हेतु मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान से अपेक्षा की गयी ।

मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा पेयजल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के कार्यों में विभागों द्वारा जो प्रगति सूचित की गयी उसकी संकलित सूचना का प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण संलग्नक-2 के रूप में दृष्ट्य है । प्रस्तुतीकरण में दो मुख्य बिन्दुओं को समाहित किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त जिन बिन्दुओं पर चर्चा की गयी और जो नीतिगत निर्णय लिये जाने की सहमति बनी उनका विवरण निम्नवत् है :-

1. सर्वप्रथम मुख्य सचिव महोदय ने उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने राज्य में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निम्न अपेक्षाएं की गयी हैं :-

(क) पेयजल समस्या के तात्कालिक निराकरण हेतु जनता को टैंकर के माध्यम से पेयजल वितरित किया जाय । क्षतिग्रस्त योजनाओं की तत्काल मरम्मत करायी जाये । नौलों/ धारों के पुनर्जीवन कार्य हेतु कार्यवाही की जाय । निर्माणाधीन योजनायें, जिनमें अधिकांश कार्य हो चुके हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाय ।

(ख) पेयजल समस्या के दीर्घकालीन निदान हेतु महत्वपूर्ण नदियों में Catchment Area के कार्य कराये जायें, जिसके अन्तर्गत चैकडैम बनाये जायें, वनीकरण जैसे अन्य उपचार किये जायें, वर्षा जल संग्रहण को प्रोत्साहित किया जाय । रिजर्व फॉरेस्ट के अन्तर्गत जो जल स्रोत स्थित

MW

हैं, वन विभाग द्वारा उनके संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु कार्यवाही की जाय ।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जल संस्थान द्वारा सूख रहे पेयजल स्रोतों की सूची समस्त जिलाधिकारियों को भेजी जाय और उनसे अनुरोध किया जाये कि भारत सरकार द्वारा संचालित "नरेगा" कार्यक्रम के अन्तर्गत जल सम्बर्द्धन के कार्यों को सम्मिलित करते हुए कार्यवाही की जाय । ( कार्यवाही: जल संस्थान/वन विभाग/समस्त जिलाधिकारी)

सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा अवगत कराया गया कि वनीकरण का लाभ लगभग 10 वर्ष के बाद प्राप्त होगा, अतः यह समीचीन होगा कि जल स्रोत सम्बर्द्धन एवं जल संरक्षण हेतु Staggered Trenching का कार्य किया जाय, जिसके लाभ 02 वर्षों के अन्दर मिल जायेंगे । यह भी निर्णय हुआ कि पहले ऐसे स्थलों का चयन किया जाय, जिनमें सबसे अधिक जन संख्या पेयजल समस्या से प्रभावित हो रही है ।

बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि वन विभाग द्वारा जल संस्थान स्तर से पूर्व में प्रथम चरण में भेजी गयी सूची (231+500) 731 स्थलों में जलस्रोत संवर्द्धन की कार्यवाही करने हेतु एक कार्ययोजना बनाकर 'नरेगा' कार्यक्रम के माध्यम से उसके वित्त पोषण हेतु कार्यवाही की जाय । यह भी स्पष्ट किया गया कि 'नरेगा' कार्यक्रम के अन्तर्गत यदि कार्यस्थल 08 कि०मीटर से अधिक दूरी पर स्थित हो तो ऐसी दशा में यात्रा व्यय भी देय होता है । ( कार्यवाही: सचिव, ग्राम्य विकास/समस्त जिलाधिकारी )

निदेशक, Uttarakhand Space Application Centre द्वारा विगंत कराया गया कि उनके द्वारा रिस्पना Catchment का कार्य किया गया है उनके द्वारा किये गये कार्यों के बारे में उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया गया । उनका यह मत था कि रिस्पना में कैचमेंट कार्य करने हेतु बालोंगंज के आस-पास का क्षेत्र उपयुक्त होगा ।

मुख्य सचिव महोदय ने यह भी निर्देशित किया कि कोसी नदी एवं रिस्पना नदी में जल संवर्द्धन के कार्यों की कार्ययोजना सिंचाई विभाग द्वारा बनायी जाय एवं उसके सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जाय । ( कार्यवाही: सिंचाई विभाग )

अपर मुख्य सचिव महोदय ने यह प्रेक्षा की कि जलागम द्वारा जो कार्य किये गये हैं उससे जल स्रोतों पर क्या प्रभाव पड़ा है । यह अपेक्षा की गयी कि N.R.A.A. के अन्तर्गत शीघ्र एक Prospective Plan बनाया जाय । ( कार्यवाही: जलागम विभाग )

2. विचार-विमर्श के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा जिन-जिन स्थानों पर नई सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, उनके द्वारा ब्लास्टिंग करके मलवा नीचे की ओर डाल दिया जाता है जिसके कारण पेयजल स्रोत



प्रभावित हो रहे हैं । अपर सचिव, वन ने अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत विकास कार्यों हेतु ब्लास्टिंग पूर्णतया प्रतिबंधित है । इसके अतिरिक्त मलवा का निपटान एक स्थान पर किये जाने के दिशा-निर्देश भारत सरकार द्वारा जारी किये गये हैं । मुख्य सचिव महोदय ने लोक निर्माण विभाग से यह अपेक्षा की कि उपरोक्त दोनों बिन्दुओं की व्यवहारिकता का आंकलन करने के बाद स्थिति से अवगत कराया जाय ।

( कार्यवाही: लोक निर्माण विभाग )

जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क निर्माण के कारण जो पाइप लाइनें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं उनके सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग से रु0 12.21 करोड की धनराशि प्राप्त होनी शेष है । अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अभी तक पेयजल निगम एवं जल संस्थान द्वारा मांग की गयी धनराशि के सापेक्ष कुल रु0 1.3 करोड की क्षति का सत्यापन हो चुका है । उन्होंने यह भी अवगत कराया कि यह धनराशि नॉन-प्लान से दी जानी है जिसके लिये वित्त विभाग द्वारा प्रेक्षाएं की जा रही हैं जिसके कारण बिलम्ब हो रहा है ।

मुख्य सचिव महोदय ने यह अपेक्षा की कि यह धनराशि तत्काल जल संस्थान एवं पेयजल निगम को उपलब्ध करवा दी जाय जिससे क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की मरम्मत करके पेयजल समस्या का निदान किया जा सके ।

( कार्यवाही: लोक निर्माण विभाग )

अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि Border Road Organisation द्वारा भी जो सड़कें बनायी जा रही हैं, उनके द्वारा पेयजल योजनाओं को जो क्षति हो रही है, उसके लिये Border Road Organisation से सम्पर्क कर धनराशि प्राप्त की जाय ।

( कार्यवाही: जल संस्थान )

3. ग्राम सभाओं द्वारा संचालित पेयजल योजनाओं का रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है । सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा अवगत कराया गया कि एकल गांव पेयजल योजना के रखरखाव हेतु रु0 32.00 करोड की धनराशि इस वित्तीय वर्ष में दी जानी है । मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को ऐसी पेयजल योजनाओं हेतु अवमुक्त धनराशि के सदुपयोग को सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें ।

( कार्यवाही: सचिव, ग्राम्य विकास )

4. इस बिन्दु पर भी विचार-विमर्श किया गया कि हैण्ड पम्प के रखरखाव का दायित्व किसका होना चाहिये । बैठक में इस पर भी विचार हुआ कि ग्राम सभा द्वारा ही हैण्डपम्प का रखरखाव किया जाना चाहिये ।

5. विद्युत कटौती एवं लो-वोल्टेज की समस्या: मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पेयजल आपूर्ति हेतु अधिष्ठापित विद्युत संयोजनों में निरन्तर विद्युत आपूर्ति की जाये तथा पेयजल व्यवस्था से सम्बद्ध विद्युत संयोजनों को विद्युत कटौती से मुक्त रखा जाय । ( कार्यवाही: सचिव, ऊर्जा )

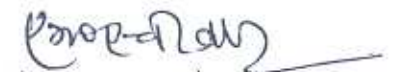
#### अन्य विषय:

शासकीय भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग योजना अपनाये जाने के लिये आगणन में व्यवस्था की जाये तथा जो पुराने भवन हैं, उनमें सनै:-सनै: रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाय । अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बीजपुर गेस्ट हाऊस, सचिवालय, राज भवन, मा0 मुख्य मन्त्री आवास, केदारपुरम आवासीय योजना में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जा रही है ।

मुख्य सचिव महोदय ने अपेक्षा की कि वर्षा जल संग्रहण के अधिक से अधिक उपयोग हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय तथा निजी भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग को अपनाने हेतु भवन स्वामियों को प्रोत्साहित किया जाय । ( कार्यवाही: समस्त विभाग )

मुख्य सचिव महोदय ने यह भी निर्देशित किया कि आगामी बैठकों में सचिव, नगर विकास एवं सचिव, आवास को भी प्रतिभाग किये जाने हेतु आमन्त्रित किया जाय तथा नगरीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के अधिक से अधिक उपयोग हेतु प्रोत्साहित करने हेतु रणनीति बनायी जाय ।

अन्त में सचिव पेयजल द्वारा मुख्य सचिव महोदय एवं उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त की गयी ।



(एम.एच. खान)

सचिव पेयजल

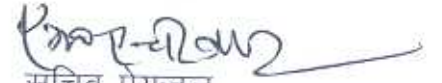
पृष्ठांकन संख्या...386.....ए.पी.एस./स.प्र.जे.ज./2009 दिनांक 10 जून 2009

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ ।
2. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
3. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
4. सचिव, सिंचाई/लघु सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन ।
5. सचिव, जलागम, उत्तराखण्ड शासन ।
6. सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन ।
7. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।



9. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
10. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम विकास परियोजना, देहरादून ।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून ।
12. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून ।
13. विभागाध्यक्ष एवं मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून ।
14. विभागाध्यक्ष एवं मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून ।
15. मुख्य अभियन्ता-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
16. सीनियर इन्फोरमेशन ऑफिसर, एनआईसी, देहरादून को वैबसाईट हेतु ।
17. निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड ।
18. निदेशक, स्वजल परियोजना, देहरादून ।
19. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
20. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
21. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून ।
22. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, मसूरी ।

  
सचिव पेयजल